

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-71/2020(जीसीएमएस नम्बर 2020/00080)

1. विजयसिंह पुत्र किशनलाल, जाति गुर्जर, निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।

—अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट

उपस्थिति:-

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.06.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 306/2, 127/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, किस्म चारागाह वाके रामा पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। इस भूमि का स्वरूप चारागाह जैसा नहीं रहा है। इस भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा काशत नहीं है। उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्त के विरुद्ध दिनांक 08.03.2016 को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कब्जा शुदा आराजी से बेदखल करने एवं लगान दर 11.94 का पचास गुणा 597/-रूपये शास्ती आरोपित की गई है एवं वास्ते कायमी वसूली बेदखल एवं फसल निलामी के आदेश पारित किये हैं तथा साथ ही अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुये 60 दिन की सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश पारित किये गये हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि इस निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश की जिसे भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 26.08.2016 को पत्रावली तथ्यों के विपरित जाकर अपीलार्थी की अपील को विधि विरुद्ध तरीके से खारिज किया गया है, जो अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत जवाब को ध्यान में नहीं रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किये जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मौके की सही स्थिति का एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि कानूनन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय पारित करने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति ट्रेसपासर है या नहीं परन्तु अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने इन सब बातों को ध्यान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

P.T.O.

(2)

में नहीं रखते हुये अपीलार्थी निर्णय पारित किये है जो निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलार्थी निर्णय दिनांक 26.08.2016 व उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2016 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 306/2 रकबा 1 बीघा व खसरा नम्बर 127/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 2 बीघा 5 बिस्वा पर काश्त कर अतिक्रमण किया गया है जबकि कानूनन राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्त द्वारा उक्त राजकीय चारागाह भूमि पर सम्वत् 2072 में खरीफ के समय भी अतिक्रमण किया गया था जिसे तत्समय बेदखल करने के पश्चात् पुनः चारागाह भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है जिससे वह पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थी आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलार्थी आदेश दिनांक 26.08.2016 को यथावत रखा जाता है।


(डॉ० प्रवीण कुमार)
अति.सभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अति.सभागीय आयुक्त,
जयपुर।